लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 16 - 31 जुलाई, 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक - 70

"स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है।"

: स्वामी दयानंद

जंगल सफारी से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा

2

औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप नए स्टार्टअप

5

आम उत्सव

8

बरसात का कहर चाक चौबंद रहा प्रशासन

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सारे काम छोड़कर निरंतर लिया हालात का जायजा

विशेष प्रतिनिधि

सावन के दूसरे सप्ताह, प्रदेश के अधिकांश मैदानी इलाकों में जोरदार बारिश हुई। पड़ौसी राज्य हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भी खूब बरखा पड़ी। बरसाती नदियों के जरिए आए पानी से राज्य का जन जीवन हलकान रहा। पानी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई और बंदोबस्त चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान अपने सभी व्यस्त कार्यक्रम छोड़कर निरंतर हालात का जायजा लिया और कहा कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए।

अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर जिलों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक रही। स्थानीय लोगों को नदियों के पास न जाने की सलाह दी गई। यमुना, घग्घर व अन्य छोटी नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होती रही जिसने लोगों की धड़कने बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश होने से नदियां लबालब रही। पंचकूला के शहरी क्षेत्र में घग्गर का विस्तार देखा गया। पानी लगातार बढ़ता गया तो किसानों के साथ प्रशासन की चिंता बढ़ती चली गई। नदी के निचले इलाकों को खाली करवाने के लिए कहा गया। नरवाना ब्रांच और

एसवाईएल में भी पानी अपनी पूरी क्षमता तक रहा। स्थानीय प्रशासन की ओर से बोरियों में मिट्टी भरवाकर तैयार रखी गई जिसका अनेक स्थानों पर इस्तेमाल भी किया गया। उपायुक्तों ने अपने-अपने जिलों में हर स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखी। किसी इलाके में पानी भरने की स्थिति में लोगों को रेस्क्यू करने के साथ-साथ भोजन के पैकेट पहुंचाना व स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की तैयारी रखी गई।

पंचकूला की उपायुक्त को निर्देश रहे कि पिंजौर -बद्दी सड़क पर पुल टूटने के कारण लोगों को हो रही परेशानी का समाधान निकालने व हिमाचल के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके अन्य मार्ग की व्यवस्था करवाने के प्रयास करें।

अंबाला में नदियों में पानी ज्यादा रहा। घग्घर नदी का जलस्तर 16,500 क्यूसिक रहता है, जबकि उस दौरान 21 हजार क्यूसिक पानी रहा। टांगरी नदी का जलस्तर भी स्वाभाविक 13 हजार क्यूसिक की बजाय 21 हजार क्यूसिक पार कर गया। इसके अलावा, मारकंडा नदी का जलस्तर, सेफ जोन 50 हजार क्यूसिक है जबकि इस दौरान 50 हजार क्यूसिक पानी रहा। प्रशासन ने पूरी तैयार रखी और निचले इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। भोजन की व्यवस्था की गई व गांवों में मुनादी करवाई गई कि लोग नदियों के पास न जाएं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना की टुकड़ी नरवाना ब्रांच पर तैनात की गई।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौशल्या डैम जाकर जल स्तर का आकलन किया। उन्होंने बताया कि बढ़े जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के गेट खोले गए हैं और 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हथिनी कुंड बैराज पर एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जबकि वहां 300,000 क्यूसेक पानी पर अलर्ट होता है।

घग्घर का पानी रहा खतरे के निशान पर

पंचकूला में औसत से कई अधिक बारिश हुई। घग्घर नदी का पानी खतरे के निशान पर पहुंचने से साथ लगते इलाकों को खाली करवाया दिया गया। मारकंडा नदी में वर्ष 1978 में 256.4 मीटर पानी रिकॉर्ड किया गया था, जबकि इस दौरान 255 मीटर से अधिक पानी रहा। यमुनानगर में भी यमुना नदी के जल स्तर को देखते हुए इलाकों को खाली करवाने की प्रक्रिया अमल में लाई गई। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरफ और एनडीआरफ टीमों को तैनात किया गया।

G20 भारत 2023 INDIA

अलर्ट रही एनडीआरएफ की टीमें

भारी बारिश के कारण यमुना और उसकी सहायक नदियों और मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने के चलते हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर और करनाल सहित कई जिले गंभीर रूप से प्रभावित हुए। स्थिति की तात्कालिकता को समझते हुए, पुलिस महानिदेशक हरियाणा, पीके अग्रवाल ने आईआरबी हरियाणा पुलिस के राज्य आपदा प्रतिं या बल (एसडीआरएफ) को इन जिलों में बचाव कार्यों की कमान संभालने का निर्देश दिया।

बचाव प्रयासों को संभालने के लिए प्रशिक्षित 74 पुलिस कर्मियों की एक समर्पित टीम तैनात की गई। डीजीपी के निर्देशों के अनुसार, बचाव कार्यों के समन्वय और नेतृत्व के लिए प्रत्येक प्रभावित जिले में दो पुलिस उपाधीक्षक (डीएसएसपी) और एक निरीक्षक नियुक्त किया गया है।एसडीआरएफ की टीमों ने अथक परिश्रम करते हुए लगभग 800 व्यक्ति यों को बचाया गया तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया।

अंबाला से सात मार्ग बंद

बारिश की वजह से अंबाला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। गृहमंत्री अनिल विज ने मैदान पर उतरकर लोगों की मदद की और प्रशासन को चुस्त रखा। उन्होंने बरसाती नदी टांगरी व अन्य नालों का जायजा लिया। यहां का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा पानी में डूब गया। मुख्य मार्गों को काफी नुकसान हुआ जिसके चलते अंबाला से चंडीगढ़, सहारनपुर, दिल्ली, जालंधर, हिसार, यमुनानगर, पंचकूला वाया बरवाला मार्ग बंद कर दिए गए। नेशनल हाइवे अथारिटी ने लोगों को सलाह दी है कि वे इन मार्गों से यात्रा न करें। एनडीआरएफ की टीम ने करीब दो हजार लोगों को रेस्क्यू किया जिनमें एक स्कूल की 731 छात्राएं भी शामिल रही।

पंचकूला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद व सिरसा से राजस्थान की ओर जाने वाली घगर नदी उफान पर रही जिसके चलते सिरसा में ओटू हैड के गेट खोल दिए गए। करनाल व पानीपत के सैकड़ों गांवों में बाढ़ जैसे हालात रहे।

ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद स्वतः होगा इंतकाल

एसडीएम और डीआरओ भी कर सकेंगे रजिस्ट्रियां

राज्य में अब तहसीलदारों के अलावा एसडीएम और डीआरओ को भी अपनी तहसीलों में संपत्ति के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। जल्द ही एक नई प्रणाली शुरू की जाएगी जिसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं भी हो सकेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। उन्होंने वेब हैलरिस में म्यूटेशन का स्वचालित जेनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया।

पोर्टल के लॉन्च होने से अब किसी भी संपत्ति/जमीन का इंतकाल (म्यूटेशन) रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा। इसके साथ ही म्यूटेशन की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसे कोई भी चेक कर

सकता है। म्यूटेशन पर कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिनों की समयावधि दी जाएगी।

अगर कोई 10 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करवाता है तो म्यूटेशन को विवादित माना जाएगा और इंतकाल नहीं होगा। यदि कोई आपत्ति नहीं आई तो स्वतः इंतकाल (म्यूटेशन) हो जाएगा। फिलहाल किसी भी जमीन या संपत्ति की बिक्री, मॉर्टगेज विद पोजेशन, पारिवारिक हस्तांतरण और उपहार का म्यूटेशन किया जाएगा।

अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू :

शहरी स्थानीय निकाय और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा राज्यभर में अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इसके लिए कानूनों और नीतियों में भी संशोधन की आवश्यकता है। अभी तक सरकार के पास लगभग 2000 अनियमित कॉलोनियों की सूची है, जिन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

विधुरों को भी मिलेगी पेंशन

हरियाणा में 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2750 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। पेंशन का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत, दूसरी श्रेणी में 40-60 वर्ष की आयु के विधुर को भी शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी, ऐसे सभी को 2750 रुपए की पेंशन का लाभ मिलेगा। इस पेंशन योजना से लगभग 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा तथा राज्य सरकार पर इससे सालाना 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

संपादकीय

खुलेगा सुख का नया संसार

गत दो सप्ताह में हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए हैं जो प्रदेश के सामान्य जन के लिए सुख व समृद्धि का संसार खोलने जा रहे हैं।

इनमें रजिस्ट्री के साथ-साथ 'इंतकाल' एक ऐसी योजना है जो हजारों लोगों के लिए राहत भरी है। यही स्थिति पेंशन-वृद्धि के क्षेत्र में है।

इसी तर्ज पर आरंभ किया गया 'ग्रामदर्शन' पोर्टल भी विकास की प्रयोगधर्मिता के क्षेत्र में अनूठी पहलकदमी है। इसे प्रशासनिक क्षेत्रों में भी एक व्यापक सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहलकदमी माना जा रहा है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच सीधा संबंध स्थापित करना है। यह पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग, शिकायत व सुझाव देने का एक सुविधानजक एवं सरल माध्यम है। इस पोर्टल पर ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। सभी विभागों के अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की प्राथमिकता हर हाल में लोगों की शिकायतों का निवारण करना है।

इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने गांव (जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो) के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकेगा। ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांगें सीधे सरपंच, पंचायत समिति, जिला सदस्य, परिषद-सदस्य, विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र के ही सुझाव डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे। जिन्हें संबंधित जनप्रतिनिधि संस्तुति के साथ आगे बढ़ा सकेंगे।

ग्राम दर्शन पोर्टल में भेजे गए सुझाव या शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एक आईडी 'जेनरेट' होगी जो संबंधित आवेदक को एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक को समय-समय पर सुझाव या शिकायत पर हुई कार्रवाई की अपडेट सूचना एमएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी। यह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

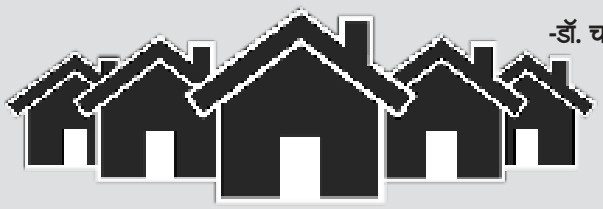

मेरा बिल-मेरा अधिकार

कर दाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सहित देश के पांच राज्यों में 'मेरा बिल-मेरा अधिकार' योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ता को सामान की खरीददारी की रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और 30 करोड़ रुपए के कॉर्प्स फंड से ड्रा ऑफ लॉट्स के जरिए उपभोक्ताओं को इनाम भी मिलेंगे।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 'मेरा बिल-मेरा अधिकार' योजना से उपभोक्ताओं में सामान की खरीददारी करते समय विक्रेता से बिल मांगने की प्रवृत्ति विकसित होगी। साथ ही उपभोक्ता व सरकार के बीच एक मज़बूत भावना भी विकसित होगी। उन्होंने कहा कि देश की कर प्रणाली को सरल बनाने तथा इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने में जीएसटी एक बेहतरीन व्यवस्था साबित हुई है। इससे नागरिकों पर कर का बोझ कम हुआ है तथा औद्योगिक क्षेत्र की सुविधाएं भी बढ़ी हैं।

चौटाला ने कहा कि जीएसटी की मदद से राजस्व प्राप्ति 64 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 1.50 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। जीएसटी के दायरे में नए क्षेत्रों को जोड़ इसे अढ़ाई करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।

उत्पाद एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र सिंह कल्याण ने कहा 'वन नेशन-वन टैक्स' के उद्देश्य के साथ लागू किया गया जीएसटी, टैक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। निर्यातकों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों, कृषि एवं उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ मिलने के साथ ही जीएसटी का अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ा है।

-संवाद ब्यूरो

जंगल सफारी से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा

गुरुग्राम क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके बनने के बाद एक ओर जहां अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम व नूह क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को 7 दिन के अंदर-अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम और नूह जिलों के अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ भूमि को जंगल सफारी पार्क के लिए चिह्नित किया गया है। बैठक में कई विषयों को लेकर विचार-विमर्श किया गया है। जंगल सफारी पार्क को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा, पहले चरण को पूरा करने के लिए लगभग 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि जैव विविधता पार्क अवधारणा के अनुरूप अरावली सफारी पार्क परियोजना के डिजाइन संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए दो चरण की निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है। इस प्रक्रिया में ऐसी सुविधाओं के डिजाइन व संचालन में अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाली दो कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। एक कंपनी द्वारा पार्क को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया गया। जल्द ही पीएमसी का चयन कर लिया जाएगा।

मनोहर लाल ने कहा कि जंगल सफारी में सभी प्रकार के जानवर तथा पक्षियों की प्रजातियां लाने का प्रयास है। वन्यजीवों की स्वदेशी प्रजातियों के अलावा यहां की जलवायु में रह सकने वाले जानवरों पर भी अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर झील की तरह माइग्रेटिड बर्ड के लिए झील की व्यवस्था हो, इस पर चर्चा की गई। इस प्रकार के जंगल सफारी विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित करने के केंद्र होते हैं। सरकार का भी यह प्रयास है कि ऐसी प्रजातियों को सफारी पार्क में संरक्षित रखा जाए।

राखी गढ़ी संग्रहालय का डिजाइन

राखीगढ़ी में म्यूजियम बनाने को लेकर बैठक में चर्चा हुई, जिसमें राखीगढ़ी की पुरानी सभ्यता को सुरक्षित रखना व उसे विकसित करने को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ मिलकर हरियाणा सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साइट संग्रहालय और राखीगढ़ी गांव के भीतर पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना का प्रस्ताव तैयार किया है, जो लगभग फाइनल हो चुका है। बैठक में विभिन्न विषयों की टाइमलाइन तय की गई है। पीएमसी नियुक्त करने के लिए 15 जुलाई तक टेंडर होगा और 15 अगस्त तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दिसंबर माह तक तक संग्रहालय की शुरुआत हो सके, इसके लिए सभी संबंधित विभागों को तेजी गति से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा छोटा राज्य है, लेकिन यहां पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। सरस्वती काल की सभ्यता के अवशेष भी हरियाणा के कई स्थानों पर हैं। इन सबको भी संरक्षित व सुरक्षित रखने के लिए सरकार प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आज जनता महसूस करती है कि जिस तरह की शासन व्यवस्था अब उन्होंने देखी हैं, पहले कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी बनेंगी। आज हर वर्ग को महसूस होता है कि हमारी आवश्यकताओं की जानकारी होते ही सरकार उनकी डिलीवरी उनके घर द्वारा पर देती है। जन संवाद कार्यों के माध्यम से लोग हमें बता रहें हैं कि वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शी ढंग से बिना किसी भेदभाव के पात्र व्यक्तियों को उनके अधिकार दे रही है।

-संवाद ब्यूरो

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई, 2023 तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। अवार्ड की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर की जाएगी।

हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई, 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी, अब छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक

पुलिस विभाग के लिए तीन राज्य पुरस्कारों की घोषणा

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में तीन राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे पहले, मंत्रिमंडल ने हरियाणा पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट अन्वेषण, वीरता और प्रशासनिक कर्तव्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए तीन राज्य पुलिस पुरस्कारों नामतः मुख्यमंत्री वीरता पदक, गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी उत्तम सेवा पदक को मंजूरी दी थी।

एसओपी के अनुसार, मुख्यमंत्री वीरता पदक और गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक के विजेताओं को क्रमशः दो लाख रुपए और एक लाख रुपए का एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया जाएगा। ये पदक विजेताओं की वर्दी की बाईं जेब के ऊपर प्रदर्शित होंगे। पुलिस कर्मियों के लिए ग्रुप-बी और सी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सेवा में छह महीने का विस्तार देने का भी प्रावधान किया गया है।

डीजीपी उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वाले कर्मियों को पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र/ स्क्रॉल सहित पदक तथा 50 हजार रुपए का एकमुश्त नकद इनाम मिलेगा।

सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति नियमों को मंजूरी

हरियाणा सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के नियमों को मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यों के प्रबंधन और निगरानी के लिए गठित एडहॉक कमेटी का कार्यकाल 18 महीने बाद समाप्त होने जा रहा है, इसलिए हरियाणा सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए हरियाणा में गुरुद्वारों का चुनाव कराना आवश्यक है और इसी उद्देश्य के लिए, उपरोक्त नियमों को अधिनियमित किया गया है।

लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी

हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी 2019 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। न्यूनतम क्षेत्र और न्यूनतम पहुंच मार्ग के साथ विभिन्न व्यवसाय और विभिन्न श्रेणी के वेयरहाउस के पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं।

इनलैंड कंटेनर डिपो अब न्यूनतम 20 से 25 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, आवश्यक न्यूनतम पहुंच सड़क 50 फीट होगी जो कि पहले 2 एकड़ और 30 फीट की पहुंच सड़क की शर्त थी। संशोधन के बाद 25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आईसीडी स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पहुंच सडक़ 60 फीट होगा। कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए न्यूनतम निवेश रुपये 15 करोड़ और न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता 0.5 एकड़ होगी और न्यूनतम पहुंच सडक़ 33 फीट होगी।

उद्यम और रोजगार नीति

हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति के तहत अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। नए संशोधनों के अनुसार, वैश्विक बाजार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अन्य गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों सहित इकाई के परिसर से बंदरगाह / एयर कार्गो / अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक परिवहन लागत की अदायगी के लिए माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।

योजना की लागू होने की प्रभावी तिथि 1 जुलाई, 2023 होगी जिसका अर्थ है कि वास्तविक निर्यात 1 जुलाई, 2023 को या उसके बाद किया जाना चाहिए, यह उठान के बिल के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यह नीति राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और 5 लाख नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से अधिसूचित की गई थी।

पानी का शुल्क वसूलेंगे महिला समूह

जल जीवन मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने की योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत, पानी के शुल्क की बिलिंग ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है, जो पोर्टल पर ऑनलाइन बिल भेजने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को जोड़ेगी। पानी के बिलों के वितरण और शुल्क का संग्रहण एसएचजी सदस्यों द्वारा समय-समय पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। वर्तमान में, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के 143 ब्लॉकों में 57,030 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 5,8 5,146 परिवारों को जोड़ा है।

महिला पेंशन योजना में बदलाव

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है।

नए संशोधनों के अनुसार, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद महिलाओं को पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलेगा। विधवा पेंशन 60 वर्ष की आयु तक स्वीकृत की जाएगी और उसके बाद, विधवा पेंशन को पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा और लाभार्थी जीवन भर भत्ता प्राप्त करता रहेगा।

'स्पोर्ट्स इवेंट्स' की परिभाषा निर्धारित

हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ियों (समूह ए, बी और सी) सेवा नियम में संशोधन किया गया है। नए संशोधनों के अनुसार, अब 'स्पोर्ट्स इवेंट्स' का अर्थ खेलों की सभी प्रतियोगिताएं हैं, जो भार वर्ग तक सीमित नहीं होंगी। पहले विभाग की किसी भी नीति में 'इवेंट' की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी।

यह संशोधन 'स्पोर्ट्स इवेंट्स' की परिभाषा को स्पष्ट करके उन खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है जिनकी प्रतियोगिताएं ओलंपिक/ राष्ट्रमंडल/एशियाई खेलों में नहीं खेली जाती हैं लेकिन राष्ट्रीय खेलों/राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी नहीं खेली जाती हैं। ऐसे खिलाड़ी अब खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा नियम

हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम के संबंध में मंजूरी दी गई है। इससे जिला स्तरीय परिषदें विशेष जिले के उद्योगपति का समय और लागत बचाएंगी और यह प्रत्येक जिले और ब्लॉक में उद्योगों की वृद्धि को देखते हुए निकट भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है। कॉउन्सिल या डिस्ट्रिक्ट कॉउन्सिल, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए वेब पोर्टल पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सहित अपने काम-काज से संबंधित बुनियादी जानकारी अपलोड करेगी।

पंचायती राज नियम में संशोधन

हरियाणा पंचायती राज नियम 1995 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नए नियम के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों और दायित्वों के लिए अपने फंड का उपयोग करने के लिए अधिकृत होंगी। हालांकि, यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को प्रदान की गई किसी भी तरह की ग्रांट-इन-ऐड का उपयोग विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।

सात जातियां अनुसूचित वर्ग में शामिल

हरियाणा पिछड़ा वर्ग अधिनियम में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार ने हरियाणा की 7 जातियों (अहेरिया अहेरी, हेरी हरि, थोरी तुरी और राय सिक्ख) को हरियाणा राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति आदेश में संशोधन किया था। चूंकि इन जातियों को हरियाणा पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2016 में बीसी ए श्रेणी में भी सूचीबद्ध किया गया था, इसलिए इन 7 जातियों को हरियाणा पिछड़ा वर्ग अधिनियम की बीसी ए श्रेणी की सूची से हटाया जा रहा है। जोगी और जंगम अलग-अलग जातियां हैं। जोगी जाति क्रम संख्या 31 पर यथावत रहेगी जबकि जंगम जाति क्रमांक 72 पर नई प्रविष्टि के माध्यम से जोड़ी जाएगी।

-संवाद ब्यूरो

हरियाणा योग आयोग की सलाह पर पतंजलि से प्रशिक्षित योग साधकों को 11 हजार रुपए के मानदेय पर योग सहायक लगाया था, जिन्हें अब एचकेआरएन के तहत लाकर मानदेय 17 हजार रुपए किया गया है।

राज्य सरकार के सामने भूस्वामियों के हित सर्वोपरि हैं और ऐसे भू स्वामियों जिनकी जमीनों से बिजली लाइनें डाली जा रही हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए पॉलिसी बनाकर नियमानुसार मुआवज़ा प्रदान किया जाए।

बागवानी को तीन गुणा करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों के साथ किया संवाद

मनोज प्रभाकर

प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार ने वर्ष 2030 तक वर्तमान में कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7 प्रतिशत के बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने तथा उत्पादन को तीन गुणा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2022-23 में बागवानी की विभिन्न स्कीमों के तहत 25 हजार लाभग्राहियों को 166 करोड़ 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है।

बीज से बाजार तक किसानों के साथ

खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केन्द्र बिन्दु हैं। सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है। बुवाई से पहले और बुवाई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी, फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक यानी बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि किसान जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें और रासायनिक उर्वरक व खतरनाक कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करें।

फसल समूहों को किया गया चिह्नित

बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत 1763 गांवों में 393 बागवानी फसल समूहों की पहचान की गई है। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक एफ.पी.ओ का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक क्लस्टर में आपूर्ति श्रृंखला बागवानी उपज के विपणन और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए एक एकीकृत पैक हाउस भी स्थापित किया जा रहा है।

बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग नीति बनाई है। इस नीति के तहत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे उद्योगों की स्थापना से किसानों को उनकी पैदावार के और अधिक लाभकारी मूल्य मिलेंगे। इस नीति के तहत लगभग 94 करोड़ रुपए की राशि से कुल 33 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है और लगभग 116 करोड़ रुपए की लागत की 44 अन्य परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, जो इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएंगी।

भावांतर भरपाई योजनाः

बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की है। इससे बाजार में फलों व सब्जियों के भावों में गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त किया गया है। इसमें 21 बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक 9,485 किसानों को 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है।

उत्कृष्टता केंद्र :

इजराइल और हरियाणा की जलवायु व भूमि में अनेक समानताएं हैं। वहां की टैक्नोलॉजी हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है। इसलिए हम प्रदेश में फलों, सब्जियों व फूलों की खेती तथा मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में इजराइल की तकनीक को अपना रहे हैं। नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 14 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये गये हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य में तीन नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पंचकूला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्याज के लिए पिनगवां, नूह में तथा फूलों के लिए मुनीमपुर, झज्जर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

बागवानी फसलों की आसानी से बिक्री व उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 1,000 किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) बनाए जाने का लक्ष्य है। अब तक 731 किसान उत्पादक समूह बनाए जा चुके हैं। इन समूहों द्वारा 150 इंटीग्रेटेड पेक हाउस बनाए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसान अपने फल व सब्जियों को बेचने में सक्षम होंगे।

सब्जियां उगाने पर अनुदानः

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आम, अमरूद, बेर, चीकू, लीची, आंवला, नाशपाती, आलू बुखारा, केला, पपीता, सिट्रस फल, अंगूर, अंजीर व स्ट्रॉबेरी के बाग लगाने पर प्रति एकड़ लागत का 50 प्रतिशत से लेकर 85 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। सब्जियों की खेती के एकीकृत माडल पर 50 प्रतिशत से लेकर 8 5 तक सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की खेती के लिए भी 40 प्रतिशत से लेकर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। पॉलीहाउस, हाइटेक ग्रीन हाउस बॉक-इन-टन्नल, एंटी इन्सेक्ट नेट हाउस, पॉली नेट हाउस केबल परलीन नेट हाउस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत और अनुसूचित वर्ग के किसानों को 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, मशरूम की नई प्रजातियों जैसे मिल्की मशरूम, आयस्टर, मशरूम (ढिंगरी) व शिटाके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसमें किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

नई योजनाओं से सुदृढ़ होगी पेयजल आपूर्ति

जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक में राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से 834.10 करोड़ रुपए की लागत की 795 नई पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें 104.27 करोड़ रुपए की लागत की 134 नई शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाएं भी शामिल हैं।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए पहले से मंजूर 286 कार्यों हेतु 801.48 करोड़ रुपए की राशि की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

जलभराव वाले इलाकों को करें चिह्नित

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलभराव वाले इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां हर बरसात के मौसम में जलभराव होता है, ताकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सकें। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक कोर ग्रुप

गठित करने के भी निर्देश दिए, जो अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार जलभराव की समस्या के समाधान पर विचार-विमर्श करेगा। यह कोर ग्रुप जलभराव वाली भूमि का मत्स्य पालन, तालाबों और जल निकायों के निर्माण, सिंचाई आदि में प्रभावी उपयोग के लिए योजना तैयार करेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि तालाबों की सफाई के साथ-साथ तालाब की मिट्टी के उपयोग की भी संभावनाएं तलाशी जाएं।

महाग्रामों में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली

आठ महाग्राम गांवों में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में, 29 महाग्रामों में काम प्रगति पर है और इनमें से 10 गांवों में दिसंबर 2023 तक कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी गांवों के लिए भी कार्य की गति बढ़ाई जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के फील्ड अधिकारियों को जलापूर्ति और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए प्राथमिकता आधार पर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

आवंटित पानी की स्थिति देखने के लिए डैशबोर्ड

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश में स्थापित एसटीपी की स्थिति देखने के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इसके अलावा, उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग की निगरानी भी हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसी प्रकार, विभाग की वेबसाइट पर एक और डैशबोर्ड विकसित किया गया है जो हरियाणा की प्रत्येक ग्रामीण बस्ती के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन लीटर (एलपीसीडी) आवंटित पानी की स्थिति को दर्शाता है।

25.22 लाख जलापूर्ति कनेक्शन की मैपिंग

राज्य में शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाओं के संचालन व रखरखाव हेतु राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति और सीवरेज के बिल मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को विभिन्न मापदंडों और कैशलेस विकल्पों के माध्यम से भी बिल भुगतान का विकल्प दिया गया है। जलापूर्ति कनेक्शनों को परिवार पहचान पत्र आईडी के साथ जोड़ने का कार्य प्रगति पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में 28.22 लाख कनेक्शनों में से 25.22 लाख कनेक्शनों की मैपिंग पूरी हो चुकी है।

- संवाद ब्यूरो

'प्रधानमंत्री किसान सम्मान' योजना के लाभार्थी को अब ई-केवाईसी कराने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए पीएम किसान मोबाइल ऐप लांच किया गया है।

हरियाणा सरकार ने आमजन से अपील की है कि वे अपने 10 साल पुराने आधार को अपडेट करवाएं। आधार को अपडेट करवाने से व्यक्ति को अनेक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप नए स्टार्टअप

जी-20 के देशभर में आयोजित हो रहे विभिन्न सम्मेलनों की श्रृंखला में गुरुग्राम को 3 व 4 जुलाई को दूसरा बड़े स्तर का स्टार्टअप-20 शिखर सम्मेलन आयोजित करने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा में स्टार्टअप इंडिया को लेकर सराहनीय कार्य हुआ है। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन ने वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर नवाचारों, सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

गुरुग्राम में जी-20 के स्टार्टअप-20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2016 स्टार्टअप इंडिया की पहल की थी। जिसके चलते आज देश में नए स्टार्टअप बन रहे हैं और नए इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप भारत के नेशनल एसेस्ट्स है और आज के स्टार्टअप भविष्य की फॉर्च्यून-500 कंपनियां होंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जी-20 में स्टार्टअप को शुरू करना भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई नया कदम शुरू करने से पहले जी-20 के सभी देशों की सहमति लेना आवश्यक होता है।

भविष्य की दिशा में नया रास्ता

स्टार्टअप-20 के अध्यक्ष डॉ. चिंतन वैष्णव ने शिखर सम्मेलन के प्रभाव के प्रति अपना उत्साह साझा करते हुए कहा कि स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। 22 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ सहयोग, परामर्श और अटूट दृढ़ संकल्प के दिनों का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में स्टार्टअप-20 एंगेजमेंट ग्रुप में अपनी भागीदारी जारी रखने का ब्राजील का निर्णय इस पहल के वैश्विक महत्व को और मज़बूत करता है। ब्राजील और अन्य सभी देशों की निरंतर प्रतिबद्धता नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के प्रति उनके समर्पण का उदाहरण है।

सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारीः

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के उल्लेखनीय आर्थिक पैमाने और बाज़ार क्षमता ने स्टार्टअप को वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में फलने-फूलने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोयल ने कहा कि नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना केवल व्यक्तिगत देशों की भूमिका नहीं है, बल्कि सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्री ने कहा कि विचारों के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं और वित्त पोषण तंत्र को सुविधाजनक बनाने और अनुसंधान और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

एचआरएच प्रिंस फहद बिन मंसूर द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। सऊदी अरब, 2023 तक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर की महत्वाकांक्षी राशि आवंटित करने के स्टार्टअप 20 के आह्वान का समर्थन और समर्थन करने वाला पहला देश बनकर उभरा।

-संवाद ब्यूरो

अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ा गौरव

भारत की अतिथि देवो भवः तथा वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा ने दो दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर बैठक की गुरुग्राम के होटल ग्रैंड हयात तथा ओरोना कन्वेंशन सेंटर में सफल मेज़बानी से अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल समापन समारोह में शामिल हुए और गणमान्य अतिथियों, विदेशी प्रतिनिधियों एवं स्टार्टअप उद्यमियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा को महत्वपूर्ण स्टार्टअप 20 शिखर बैठक की मेजबानी मिलना गौरव की बात है। गुरुग्राम में जी-20 के एजेंडे में शामिल स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन स्टार्टअप के पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करेगा तथा अभिनव उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देगा, जो कि भविष्य के लिए एक उत्तम संकेत है।

प्लास्टिक कचरे का सदुपयोग

प्लास्टिक कचरे का सदुपयोग करते हुए कुरुक्षेत्र स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दो विद्यार्थियों ने जहां पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी निभाई है, वहीं स्टार्टअप के साथ रोज़गार के अवसर भी सृजित किये हैं। आमजन के हित में उपयोगी उत्पाद बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले मूल रूप से कानपुर निवासी सोनल शुक्ला व दिल्ली निवासी वैभव वर्मा युवा शक्ति के लिए प्रेरणास्रोत बन रहे हैं।

गुरुग्राम के ओरोना कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन के तहत लगी प्रदर्शनी में युवा सोनल व वैभव ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट का सदुपयोग करने की सोची और खुद मशीन बनाकर उत्पादन शुरू किया। सोनल व वैभव ने बताया कि इकॉन्स्कीयस भारत में स्थित एक सामाजिक प्रभाव वाला स्टार्ट-अप है जो लोगों को उनके प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करके और उसे उपहार देने और सार्वजनिक उपयोगिता उत्पादों में परिवर्तित

करके उनके कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करता है।

उन्होंने बताया कि एक शून्य-अपशिष्ट समाज बनाने की कल्पना को साकार करने के उद्देश्य से स्टार्टअप किया और पर्यावरण संरक्षण के साथ ही स्वरोज़गार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने बताया कि हम घरों, स्कूलों और उद्योगों से एकत्र किए गए प्लास्टिक कचरे को बर्तनों, प्लांटर्स, कार्यालय की आपूर्ति और बाहरी सार्वजनिक स्थान के उत्पादों जैसे बेंच और कूड़ेदान जैसे उत्पादों में पुनर्चक्रित करते हैं। ये उत्पाद पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बने हैं, अद्वितीय व प्रभावशाली हैं और समाज में ज़ागरूकता पैदा करते हैं। अब तक उनके प्रोजेक्ट में 1,50,000 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक को लैंडफिल में जाने से रोका है और अब तक सार्वजनिक स्थान पर 500 से अधिक बेंच स्थापित की हैं।

सोनल शुक्ला और वैभव वर्मा ने बताया कि वे दोनों एनआईटी कुरुक्षेत्र से एम.टेक हैं और उनके स्टार्टअप की शुरुआत में एनआईटी कुरुक्षेत्र ने अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने भी उनके स्टार्टअप को जनहित में सराहनीय बताया और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में यह स्टार्टअप मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि उनके उत्पाद अन्य उत्पादों से न केवल सस्ते हैं, बल्कि ड्यूरेबल भी हैं।

आयुर्वेद उत्पाद

सोनीपत से आयुर्वेद के डॉ अनिरुद्ध सेहरा ने नौकरी करने की बजाए अपने आयुर्वेद का स्टार्टअप शुरू किया है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में लगी प्रदर्शनी में शामिल हुए अनिरुद्ध सेहरा ने कहा कि 0 से 16 साल आयु वर्ग में कई बच्चें जिनका मानसिक विकास सही से नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि माता-पिता के अनुभवों को शामिल कर एक आयुर्वेदिक स्टार्टअप खड़ा किया है। उन्होंने बच्चों, किशोरों व बुजुर्गों के लिए फूड सप्लीमेंट तैयार किये और 2021 में मार्किट में लॉन्च किये। ये प्रोडक्ट बड़ी संख्या में लोगों की पसंद बने हुए हैं। उनके द्वारा तैयार की गई इम्युनिटी बार व स्मार्ट बार प्रोटीन लोगों की पसंद बनी है।

-दिनेश यादव,
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी

उचाना विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को जल्द ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके लिए नरवाना की सिरसा शाखा से यह पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस कार्य पर 49 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक जुलाई से यूडीआईडी कार्ड लागू हो चुका है। दिव्यांगजनों को नौकरी या अन्य किसी प्रकार का सरकारी लाभ लेने के लिए यूडीआईडी देना ज़रूरी होगा।

नशा मुक्त हरियाणा

विशेष प्रतिनिधि

नशे से व्यक्ति हर तरह से बर्बाद हो जाता है, वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से खोखला हो जाता है। प्रदेश से इस सामाजिक बुराई का उन्मूलन करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान में सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा पुलिस को कहा कि वह नशा बेचने वालों के खिलाफ़ किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने पंचकूला के इंद्रधनुष सभागार में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान एसएचओ, सीआईए प्रभारियों, थाना मुंशी और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सहित विभिन्न पुलिस इकाइयों के अधिकारियों व कर्मियों को संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के मुद्दे पर 411 थानों के लगभग 1200 एसएचओ, सीआईए प्रभारियों, थाना मुंशी से नशे की रोकथाम के लिए सीधा संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने पुलिस बल की उनके अथक समर्पण के लिए सराहना की और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को पुलिस स्टेशनों में तैनात कर्मियों के बराबर एक महीने में अधिकतम 20 डेली देने की घोषणा की। उन्होंने कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों के लिए 200 रुपए, एएसआई के लिए 250 रुपए, एसआई के लिए 300 रुपए और इंस्पेक्टरों के लिए 400 रुपए मासिक मोबाइल भत्ता देने की भी घोषणा की। इसके अलावा, सीएम ने यह भी घोषणा की कि पुलिस स्टेशनों में तैनात मुंशियों को आतिथ्य सत्कार के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस का प्रहरी एप भी लॉन्च किया और 'ऑपरेशन ध्वस्त' की प्रशंसा की।

गृह मंत्री अनिल विज ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से होने वाली समस्याओं को रेखांकित किया, जिनमें स्वास्थ्य को नुकसान, सामाजिक अस्थिरता और अपराध दर में वृद्धि शामिल है। उन्होंने इस मुद्दे पर काबू पाने के लिए एकता और सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।

आरोपियों को मिलेगी सख़्त सजाः विज

हरियाणा में नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों को सख़्त से सख़्त सजा दिलाने और मामले को मज़बूती से कोर्ट में रखने हेतु जल्द ही थाना स्तर पर लीगल ऐड मुहैया करवाई जाएगी। इस संबंध में कार्यवाई जारी है और यह लीगल ऐड व्यवस्था जल्द ही थाना स्तर पर उपलब्ध होगी ताकि 45 प्रतिशत कनविक्शन रेट को और अधिक बढ़ाया जा सके। चिट्टे का अवैध कार्य करने वाले लोगों को डेपोट करने हेतु जल्द ही केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी और इस संबंध में हल निकाला जाएगा।

- अनिल विज, गृह मंत्री, हरियाणा

राज्य सरकार का विशेष योगदान

सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2018 में नशे की समस्या का पता लगाने के लिए देशभर में हर राज्य, हर जिले में सर्वेक्षण किया गया और 254 ऐसे जिले सामने आए हैं, जिनमें ये समस्या गंभीर है या गंभीर होने के कगार पर है। इन 254 जिलों में हरियाणा के 16 जिले शामिल हैं। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान में हरियाणा सरकार निरंतर सहयोग कर रही है। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नशा बेचने वालों, तस्करों को बख्शा न जाए। वर्ष 2022 में राज्य में नशे की दवाएं बेचने वाले, तस्कर या रिटेलर से जुड़े 6044 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग 52-53 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई।

युवा वर्ग आगे आएः राज्यपाल

करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नशा संपूर्ण समाज के लिए एक बड़ी समस्या है। नशे के नाश के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आकर प्रयास करना होगा। युवाओं को आगे आकर प्रयास करने चाहिएं।

नशामुक्ति के प्रयास

- हरियाणा सरकार नशे पर रोक लगाने के लिए निरंतर योजनाएं बना रही है।
- मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए सोसाइटी की स्थापना की गई है।
- इस सोसाइटी के लिए 1 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान भी दिया गया है।
- केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। इसमें हरियाणा के 10 जिलों को शामिल किया गया था।
- 20 जून 2023 तक प्रदेश में कुल 105 नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएँ, धार्मिक संस्थाएं, सरकार के प्रतिनिधि व पुलिस अधिकारी तथा संबंधित विभागों के प्रतिनिधि इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे।
- दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने हेतु मोबाइल एप साथी बनाया है।
- आपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया है तथा पंचकूला में अंतरराज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है।
- राज्य सरकार जन जागृति के लिए विशेष ज़ागरूकता अभियान चला रही है। इसके लिए ग्राम से राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन किया है।
- अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर राज्य भर में लगभग 101 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया है।
- हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे और जहां-जहां सेंटर हैं वहां उनकी जांच स्वास्थ्य एवं खाद्य औषधि विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी ताकि वहां कोई गलत कार्य न हो सके।

जागरूकता कार्यक्रमों पर जोरः मुख्यमंत्री

हरियाणा में नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भजन, नाटकों द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के बारे लोगों को जागरूक किया जायेगा ताकि प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जा सके। इसके लिए सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर विशेष प्रचार अभियान चलाया जाएगा। इस नशा मुक्त अभियान में लोक कलाकारों द्वारा फोक, रागिनी एवं नाटक के माध्यम से हरियाणवी भाषा में लोगों को नशे की आदत को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

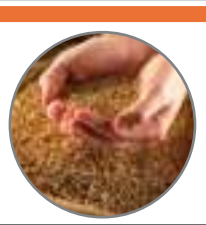

हरियाणा में राशन वितरण के तहत पांच जिलों में आटा में फोर्टिफिकेशन शुरू किया था जिसके परिणाम सकारात्मक आए हैं। एनीमिया में गिरावट आई है तथा लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।

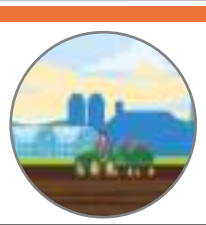

मानेसर तहसील के कासन, कुकरोला और सेहरावां गांवों की जमीन अधिग्रहण के मामले में भूमि मालिक नो लिटिगेशन पॉलिसी के तहत एक एकड़ भूमि के लिए 1000 वर्ग मीटर के बराबर भूखंड लेने के पात्र होंगे।

राहगिरी में उमड़ा करनाल

सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति किया ज़ागरूक

विशेष प्रतिनिधि

करनाल के वाल्मीकि चौक (घंटाघर) पर भव्य ढंग से 'राहगिरी कार्यक्रम' में हजारों की संख्या में युवा तथा आमजन की भागेदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं विभिन्न गतिविधियां, योग, पुलिस बैंड, मटका दौड़, स्केटिंग, क्रिकेट, रंगोली, हॉकी, बैडमिंटन, म्यूजिकल चेयर गेम, बॉक्सिंग, कबड्डी, गतका, साइकलिंग, वालीबॉल, फुटबॉल, खो-खो, जिमनास्टिक, एरोबिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट व अन्य खेल गतिविधियों में युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शृंखला में जहां स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, वहीं प्रसिद्ध कलाकारों की गायकी भी सुनने को मिली। अंतरराष्ट्रीय रेसलर दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले शूटिंग के खिलाड़ी अनीश भानवाला तथा लंदन ओलम्पिक्स में बॉक्सिंग खिलाड़ी सुमित सांगवान भी पहुंचे।

उन्होंने कहा कि 'हरियाणा उदय' प्रोग्राम के तहत हरियाणा सरकार ने राहगिरी मैराथन को प्राथमिकता दी है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से न केवल मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि उसमें सकारात्मक सोच का भी संचार होता है। इन कार्यक्रमों से अच्छी बातें लोगों को सीखने को मिलती है। इतना ही नहीं, भाग- दौड़ की जिंदगी में मनुष्य का जीवन तनाव भरा रहता है, इससे भी छुटकारा मिलता है और मानसिक रूप से भी मज़बूती मिलती है। लोग सुबह-सुबह उठकर सड़कों पर आकर योग, खेल गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद हरियाणा सरकार ने राहगिरी जैसे कार्यक्रमों की कई वर्षों बाद पुनः शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत गुरुग्राम व पानीपत में भी यह कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। युवा शक्ति को प्रेरित करने के लिए सिरसा में ऐतिहासिक मैराथन, पानीपत में महिलाओं के लिए पिंकाथॉन व अन्य शहरों में भी ऐसे उल्लेखनीय आयोजन हुए हैं।

राहगिरी कार्यक्रम का थीम सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करना है, जिससे आम जनता स्वयं भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कार्यक्रम के माध्यम से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण तथा नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है। इन संदेशों को संत महात्माओं, ऋषि मुनियों तथा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी प्रसारित किया जा रहा है ताकि समाज में एक बदलाव आए और लोगों का जीवन सरल, सुगम और खुशहाल बने।

राहगिरी कार्यक्रम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और नियमित रूप से इससे जुड़े रहें। राहगिरी कार्यक्रम को एक सप्ताह में या 15 दिन में अवश्य आयोजित करें, कोशिश करें कि अलग-अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। राहगिरी कार्यक्रम एक राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता के लिए एक सामाजिक मेला है। ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में आपसी प्रेम भाव भी बढ़ता है तथा समाज व देशहित के बारे में अच्छी बातें निकलकर सामने आती हैं।

-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

करें योग-रहें निरोग

मुख्यमंत्री ने राहगिरी कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति व मेरा मिशन-मेरा भारत की ओर से करवाए जा रहे योगाभ्यास में भाग लिया और कहा कि सभी नागरिक योग करें और निरोगी रहें। योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ व सुखमय रखें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जूडो-कराटे प्रतियोगिता में हाथ आजमाए और प्रतिद्वंदी को पटखनी दी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के बीच जाकर उनका उत्साह बढ़ाया और खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचवाए।

मुख्यमंत्री ने राहगिरी कार्यक्रम में पौधारोपण किया और आम जनता को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मानसून का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसा मौसम पौधारोपण के लिए उपयुक्त है, इसमें हर व्यक्ति को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और दूसरों को भी पौधारोपण करने के लिए प्रेरित करें।

बाबा मस्तनाथ मठ में हरड़ पूजा

नाथ संप्रदाय देश के अति प्राचीन संप्रदाय में से एक : योगी आदित्यनाथ

मनोज प्रभाकर

अस्थल बोहर स्थित श्री बाबा मस्तनाथ मठ में हरड़ पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भेष बारह पंत योगी महासभा के अध्यक्ष महंत आदित्यनाथ योगी ने शिरकत की। नाथ संप्रदाय के पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ हरड पूजा संपन्न की गई और गुरु महाराज महंत पीर चांद नाथ योगी जी की स्मृति में आठमान भंडारा, शंखढाल व देश मेले की तिथि आयोजित तिथि सुनिश्चित की गई।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नाथ संप्रदाय अति प्राचीन संप्रदाय में से एक है। महंत चांदनाथ जी महाराज ने धर्म, देश, संप्रदाय, जनमूल्यों, जनआदर्श की पद्धति को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनका यह विशेष योगदान वर्तमान में कोई नहीं भूला सकता। उन्होंने कहा नाथ संप्रदाय का कोई भी अनुयाई भारत के किसी भी कोने में जाएगा तो उसे नाथ संप्रदाय के योगेश्वर हर जगह देखने को मिलेंगे।

संपूर्ण भारत में नाथ संप्रदाय के अनुयाई बढ़ रहे हैं धर्म के साथ-साथ दीक्षित और शिक्षित भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कोई भी सनातन धर्म का उल्लंघन न करे नाथ संप्रदाय की शिक्षा का अनुसरण कर सफलता की ओर अग्रसर रहे। महंत चांद नाथ योगी जी ने पूज्य गुरुदेव श्री श्रेयनाथ द्वारा शिक्षा चिकित्सा और

अध्यापन के क्षेत्र में जो भी प्राप्त किया उन्हीं को आधार बनाकर जीवन के अनेक उल्लेखनीय कार्यों में अपना योगदान दिया। एक योग्य गुरू से योग्य शिष्य विरासत को प्राप्त करता है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए वर्तमान महंत एवं अलवर सांसद महंत बालकनाथ जी योगी अपने गुरु चांदनाथ जी योगी के मार्ग का अनुसरण करते हुए शिक्षा चिकित्सा और अध्यात्मिक में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और नाथ संप्रदाय के राष्ट्र उत्थान के क्षेत्र में भी कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।

सांसद महंत बालक नाथ योगी ने इस विशेष पूजा में पधारने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित समस्त योगेश्वर का तहे दिल से आभार प्रकट किया।

इस अवसर पर श्री महंत पीर योगी राजनाथ उज्ञाना, श्री महंत पीर हरिनाथ योगी धनोरी, श्री महंत पीर शेरनाथ योगी सोंगल, श्री महंत पीर लहरनाथ रायसन, श्री महंत पीर शेरनाथ पेहवा, श्री महंत पीर पूर्णनाथ हीरो कलां, श्री महंत नरहरी नाथ, श्री महंत पीर पारसनाथ अम्बाला, महामंत्री चेताईनाथ हरिद्वार, बारह के महंत कृष्ण नाथ योगी, अठारह के महंत समुद्र नाथ योगी, महंत सूरज नाथ कीनू हिमाचल, प.पंचमनाथ योगी, महंत सुन्द्राई नाथ योगी सिरसा, प. केशव नाथ नाथ ढाना, भानी नाथ महत चन्द्रनाथ, गोकर्ण डेरे के महामंडलेश्वर बाबा कपिल पुरी महाराज, गांधी कैंप डेरे से सिद्ध महामंडलेश्वर विश्वेश्वरनंद महाराज, सांपला डेरे से कालिदास महाराज समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

आठों पीरों द्वारा स्वीकृत तिथि आज के दिन हरड़ पूजा में पीर महंत चांदनाथ महाराज कैलाशवासी मठाधीश बाबा मस्तनाथ मठ के आठमान व देश मेला का भंडारा संवत 2080 मिति द्वादश त्रयोदशी अश्विन मास कृष्ण पक्ष तिथि 11 और 12 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार और वीरवार को भंडारा व शंखाढाल द्वारा निश्चित हुआ।

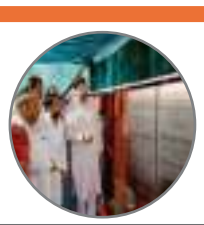

श्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकूला और कालका विधानसभा क्षेत्रों की 19 सड़क परियोजनाओं की रीकार्पेटिंग और चौड़ीकरण की आधारशिला रखकर एक महत्वपूर्ण विकास कार्य को गति दी। इन परियोजनाओं पर लगभग 56 करोड़ रुपए खर्च होंगे ।

'पदमा' के तहत उद्योग लगाने हेतु कई ब्लॉक्स में स्थानों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही बाकी ब्लॉकस में भी जगहों को अंतिम रूप देकर निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

आम उत्सव

केसर सुगंध के साथ पहुंचे बॉबे ग्रीन जैसे आम

संगीता शर्मा

पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में 7 जुलाई से 9 जुलाई तक मैंगो मेला और कुरुक्षेत्र के लाडवा के उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र पर 6 जुलाई से 8 जुलाई तक तीन द्विवसीय फल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों को आम की विभिन्न किस्मों की जानकारी देना, खेती के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के साथ-साथ अन्य फलों की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। पर्यटन विभाग तथा बागवानी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 30वें मैंगो मेले के समापन के दिन बारिश की बौछारों के बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पर्यटन मंत्री कंवर पाल मैंगो मेला में पहुंचे और वहां लगे प्रदर्शनी में आमों का जायज़ा लिया। मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दोनों ने मिलकर आम का स्वाद भी चखा। उन्होंने प्रदर्शन के लिए किए गए इंतजाम की सराहना की।

मैंगो मेले में आम की लगभग 350 किस्में प्रदर्शित की गई और मेले में हरियाणा के साथ-साथ अन्य प्रदेशों के आम उत्पादकों ने भी आम की विभिन्न किस्मों को प्रदर्शित किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने मैंगो मेले का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया था। दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी किसानों के हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में गन्नौर में 10,000 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली अंतरराष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मंडी का कार्य शुरू किया है, जहां 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार हो सकेगा। मंत्री ने कहा कि इस तरह के मेलों का आयोजन कर किसानों को आम की अधिक से अधिक किस्मों के बारे में ज़ागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम नवदीप वडाली द्वारा प्रस्तुति दी गई। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने आम मेले में पहुंच कर मेले का लुत्फ़ उठाया। मेले में लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

किसानों का कम लागत में अधिक मुनाफ़ा

उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र, लाडवा (कुरुक्षेत्र) पर तीन द्विवसीय फल उत्सव का उद्घाटन सांसद कुरुक्षेत्र नायब सिंह सैनी द्वारा दीप प्रज्जवलित करके किया गया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने समापन समारोह के दौरान कहा कि अगर किसानों को कम लागत पर अधिक मुनाफ़ा चाहिए तो उन्हें परंपरागत खेती को पूरी तरह से त्यागना होगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसान गेहूं व धान की अपेक्षा फलों के बागों से अधिक मुनाफ़ा ले सकता है। सरकार द्वारा बागों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान योजना लागू की गई है। किसान विभिन्न फलदार पेड़ों के बाग लगाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस सरकार ने कृषि विभाग के बजट को 800 करोड़ से बढ़ाकर 4 हजार करोड़ करने कार्य किया। इसी तरह पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों के बजट में पांच गुणा बढ़ोतरी करने का काम किया है।

प्रगतिशील बागवानी किसानों द्वारा प्रदर्शित की गई आम की 150 से अधिक किस्में किसानों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रही, जिनमें हाथीझूल, फजली, अंगुरदाना, गुलाबखास, बेगम पसंद, मजनू का दिल, केसर सुगंध एवं बॉम्बे ग्रीन जैसी आम की किस्में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के दौरान केंद्र पर उगाई जा रही पूसा सूर्या, नीलम, लीली, थाई मैंगों, पूसा अरूणिका, ऑस्टीन जैसी आम की 20 से अधिक किस्मों के साथ-साथ नाशपाती एवं अनार की भी कई किस्मों को किसानों के लिए प्रदर्शित किया गया था।

योजनाएं किसानों की हितकारी

सी. आई. एस. एच. लखनऊ एवं झांसी से पहुंचे फल विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार के माध्यम से आम एवं लीची की नवीनतम तकनीक अपनाकर पैदावार बढ़ाने की तकनीक बारे किसानों को विस्तारपूर्वक समझाया गया। इसके साथ-साथ कार्यक्रम में कृषि, पशुधन एवं मछली पालन, बागवानी प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य विभागों द्वारा किसानों को हितकारी योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया।

फल कार्यक्रम के आयोजक केंद्र संचालक, उप-निदेशक डॉ. बिल्लु यादव ने बताया कि केंद्र पर किसानों की प्रदर्शन के माध्यम से प्रेरित करने एवं उन्नत तकनीक बारे प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आम, नाशपाती, आड़ू, बेर, आलु-बुखारा, चीकू, लीची, अमरूद, सेब, अनार, जामुन, खुरमा, जैतुन व ड्रेगन फ्रूट इत्यादि फलों की कई किस्मों के प्रदर्शन स्थल स्थापित किए गए हैं।

आम उत्सव में 235 आम की किस्में

उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव रायपुर से उस्मान लाडवा के उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र में 235 किस्मों के आम ले कर आए। इन किस्मों को देख कर इस क्षेत्र के किसान व प्रदर्शनी देखने वाले लोग हैरान है और आम की खेती से प्रेरित हो रहे है। प्रगतिशील किसान उस्मान का कहना है कि फल उत्सव में 235 आम की किस्में प्रदर्शनी में रखी है जिसमें रसकलश, केसर शुगंद, रंगीला, यैस मैंगो, समरफिश, नीलम, रस पुनिया, हाथी झूल, अंगूरदाना, गोल्डन चौसा, दशहरी, लंगड़ा, कश्मीरी लंगड़ा चौसा, मल्लिका, अमरपाली, पत्थर, गुलाब खास, जाफरान, मासूम, रामभोग, जालिम, दिल पसंद, दिल खास, रुप की रानी, किंग कोबरा, मालदा, मोहनभोग, अम्मान, जुले खा, सुरखा कुदरत, बनका, तंबूरिया, केंड़ी, जिरया देशी, नीलम दशहरी, मैंगो करेल्या, निंबोली, हिमसागर, तिलाबंबई, बांबे ग्रीन, खपाडिया, हुस्नआरा, बारामासी, मच्छली, नेवरा, राज लोटन, बेगम पसंद, फजली, हिटलर, चाली, सन संकर, लखनवी शफेडा, शफेडाष सुकल, वर्ड मैंगो, मजनू का दिल, महक, रसीला, अल्फेंजो, जैफरानी काकडान, धनारसी लंगड़ा, शिप्या शाह पसंद, पिंजौरी लंगडा, रामकेला, केला दुगीर्लाल, गुलाब जामुन, अफसरा, हनुमान भोग, गुलपांग, प्रिंस, कश्मीरी फैजली, शाकुंभरी भोग, मैंगो ग्लास सहित अन्य किस्मे शामिल है।

सेब की दो किस्मों की पौध

हरियाणा में जल्द ही नागरिकों को अपनी ही सरजमीं पर लगने वाले सेब की खेती से मीठे-मीठे सेब खाने को मिलेंगे। इस क्षेत्र में सेब की खेती करने का सफल प्रयोग इंडो-इजरायल कृषि परियोजना के तहत उपउष्णकटिबंधीय फल केंद्र लाडवा में किया जा चुका है। इस सफल प्रयोग के बाद हरियाणा के वातावरण में अन्ना और डोरसेट गोल्डन सेब की दो किस्मों को लगाया जा सकता है। अहम पहलू यह है कि लाडवा फल केंद्र में वर्ष 2018 से दोनों किस्मों के सेब के 76 पौधे लगाए गए है और इस एक पौधे से करीब 30 से 35 किलो फल लिया गया है। इस सेब के फल को मार्केट में 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया है। इन दोनों वैरायटियों का ट्रायल सफल राहा और सार्थक परिणाम सामने आए है। इस सफलता के बाद अगले वर्ष से फल केंद्र लाडवा में सेब की अन्ना और डोरसेट गोल्डन किस्मों की पौध तैयार की जाएगी। यह पौध कोई भी व्यक्ति फल केंद्र से निर्धारित दरों पर प्राप्त कर सकता है।

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com